बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 154

जलवायु परिवर्तन से जंग

जलवायु परिवर्तन और भूमि विषय पर संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतरसरकारी पैनल (आईपीसीसी) द्वारा जारी विशेष रिपोर्ट ने वैश्विक तापवृद्धि से लड़ाई में एक नया आयाम जोड़ा है। इसने जलवायु संकट को दूर रखने के लिए भूमि के उचित इस्तेमाल को एक प्रमुख पूर्व शर्त बताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अकेले जीवाश्म ईंधन से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने मात्र से वैश्विक ताप वृद्धि को औद्योगिक युग के पूर्व के स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस पर नहीं रोका जा सकता है। पेरिस जलवायु समझौते के मुताबिक तापमान में बढ़ोतरी को इसी स्तर पर रोकना है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि मौसम में आ रहे बदलाव की प्रवृत्ति को सीमित करने के लिए जमीन के इस्तेमाल में व्यवस्थित बदलाव करने होंगे। रिपोर्ट बताती है कि जलवायु परिवर्तन के मामले में सूखा, गहन बारिश, बाढ़ के कारण जमीन का क्षरण होता है। जमीन की प्रकृति में गिरावट जलवायु परिवर्तन को इसलिए बढ़ावा देती है क्योंकि इससे उसकी कार्बन डाइ ऑक्साइड ग्रहण करने की क्षमता प्रभावित होती है।

रिपोर्ट के अनुसार मानवजनित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 23 फीसदी हिस्सा जंगल काटने, खेती, पशु चराने तथा जमीन से संबंधित अन्य गतिविधियों के कारण हो रहा है। अगर खाद्य उत्पादन के पहले और बाद की गतिविधियों मसलन कच्चे माल और उत्पादन के परिवहन, ऊर्जा खपत और खाद्य प्रसंस्करण को भी ध्यान में रखा जाए तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की हिस्सेदारी बढ़कर 37 फीसदी हो जाती है। इन हालात को बदलने के लिए वनों की कटाई रोककर नए वन लगाने होंगे और हरित क्षेत्र में इजाफा करना होगा। साथ ही जमीन को भविष्य में होने वाले नुकसान पर अंकुश लगाना होगा। सामान्य तौर पर माना जाता है कि सामान्य कार्बन चक्र से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसों में भूमि और समुद्र 50 फीसदी के जिम्मेदार है। इस स्तर को स्थिर रखने की जरूरत है, इसके लिए नए वन लगाने की गति, वनों की कटाई से तेज करनी होगी।

जलवायु परिवर्तन पर देश की कार्य योजना में कई मोर्चों पर समांतर कार्य योजना के साथ काम करने की बात सोची गई है। इसमें एक अहम घटक है वनों के माध्यम से वातावरण की ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन रोकना। इसका लक्ष्य है वनों का विस्तार करके सन 2032 तक 2.5 से 3 अरब टन अतिरिक्त कार्बन का अवशोषण करना। बहरहाल मौजूदा गति से देखें तो यह बहुत दूर की कौड़ी है। अतीत में भूमि और जल संरक्षण के लिए गए उपाय भी समय के साथ बेकार साबित हुए। एक स्थानीय एजेंसी के अनुमानों के मुताबिक देश के भौगोलिक रकबे में से करीब 30 फीसदी जमीन का स्तर बिगड़ा है। गैर कृषि भूमि, चारागाह और गांवों की जमीन बेरुखी से खराब हो रहे हैं। कृषि योग्य भूमि अतिशय सिंचाई, उर्वरकों के प्रयोग आदि से बिगड़ रही है। इन पर अंकुश लगाना होगा। जमीन का इस्तेमाल उसकी क्षमता के मुताबिक किया जाना चाहिए।

आईपीसीसी की यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब संयुक्त राष्ट्र की दो अहम मंत्रिस्तरीय बैठकें होने वाली हैं। पहली है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टु द यूएन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डिसर्टिफिकेशन (सीओपी14) जो अगले महीने दिल्ली में होगी। दूसरी बैठक कॉन्फ्रेंस ऑफ द फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (सीओपी 25) दिसंबर में चिली के सेंटियागो में होनी है। यह रिपोर्ट दोनों बैठकों को अहम जानकारी मुहैया कराएगी। रिपोर्ट के परेशान करने वाले नतीजे बताते हैं कि मिट्टी का क्षरण प्राकृतिक गति की तुलना में 100 गुना तेज गति से हो रहा है। उम्मीद है कि दुनिया के देश इसे ध्यान में रखकर अपनी जलवायु परिवर्तन की योजना पर काम करेंगे। नया लक्ष्य जमीन का क्षरण रोकने और ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन रोकने के कदम साथ उठाने का होना चाहिए। इसमें ढिलाई महंगी पड़ेगी।

अजय मोहंती

ढांचागत मंदी और घरेलू बाजार की मांग

नीति निर्माताओं के लिए चीजें स्पष्ट हैं लेकिन ढांचागत मंदी की व्याख्या कई तरह से की जा सकती है। इसमें विश्लेषण ढांचे से लेकर जमीनी हालात की समझ तक कई कारक हैं। बता रहे हैं **रथिन रॉय**

कई अर्थशास्त्री अब वह बात कह रहे हैं जो मैं पिछले काफी वक्त से कह रहा हूं- मौजूदा आर्थिक मंदी ढांचागत है। इसकी वजह कारोबारी चक्र में मंदी नहीं है। ऐसे में प्रतिचक्रीय नीतियों की मदद से इससे नहीं निपटा जा सकता है।

हालांकि यह नीति निर्माताओं के लिए तत्काल समझने की बात है किंतु ढांचागत मंदी की व्याख्या भी कई तरह से की जा सकती है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति का विश्लेषणात्मक खाका और जमीनी हकीकत की उसकी समझ कैसी है। कुछ लोगों के लिए ढांचागत का अर्थ यह है कि जिन क्षेत्रों ने अतीत में वृद्धि में बेहतर योगदान किया है उन्हें क्षेत्रवार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन दिक्कतों को हल करने के लिए क्षेत्रवार नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए ऋण तक पहुंच की समस्या को हल करना या विपरीत नीतियों को ठीक करना। यह फिलहाल वाहन क्षेत्र को लेकर हो रही चर्चा में देखा जा सकता है।

वृहद स्तर पर देखें तो ढांचागत मंदी को अक्सर आपूर्ति क्षेत्र की दिक्कत के रूप में देखा जाता है। संस्थागत संकट या निवेश में रुकावट की समस्या आती है और प्राय: सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं। ऐसे में अर्थशास्त्री प्राय: कारक बाजार (श्रम एवं भूमि बाजार), वित्तीय बाजारों (ऋण एवं पूंजी बाजार) और नियामकीय सुधारों की वकालत करते हैं। मांग में कमी के सवाल को एक चक्रीय प्रवृत्ति के रूप में देखा जाता है।

हालांकि इस रुझान को प्रमुखता तब मिली जबकि आपूर्ति क्षेत्र की आर्थिकी ने जोर पकड़ा। सन 2008 के बाद से जहां विश्व स्तर पर इसका दबदबा समाप्त हुआ है वहीं हमारे यहां यह बरकरार है। ढांचागत मांग की समस्या मौजूदा दौर में भारत की दृष्टि से विशिष्ट आर्थिक स्थिति की दिक्कतों को हल करने की दृष्टि से अहम है। मैंने पहले भी दलील दी थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था सन 1991 से मोटे तौर पर देश की आबादी के 10 से 15 फीसदी हिस्से की खपत की मांग के आधार पर आगे बढ़ी है। यह बात इस तथ्य से भी परिलक्षित होती है कि देश की आर्थिक वृद्धि के प्रमुख संकेतक इस बात से संचालित होते हैं कि लोग किस चीज की खपत करते हैं- वाहन, एफएमसीजी, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु, वित्तीय सेवाएं आदि।

सन 1991 के बाद इस वृद्धि को गति देने के लिए सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन देखने को मिला। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सन 1988 में कॉलेज के युवा लेक्चरर के रूप में मेरा वार्षिक वेतन 36,000 रुपये था। उस वक्त सबसे सस्ती कार 1.50 लाख रुपये की थी यानी चार वर्ष के वेतन के बराबर। वातानुकूलक यानी एसी 20,000 रुपये का था जो सात माह के वेतन के बराबर था, मुंबई से दिल्ली का हवाई टिकट 3,000 रुपये का था, यानी एक माह के वेतन के बराबर। आज उसी काम का वार्षिक वेतन 7.50 लाख रुपये है। वही वस्तुएं अब क्रमश: छह महीने, 10 दिन और एक दिन के वेतन में खरीदी जा सकती हैं।

जाहिर है इससे घरेलू मांग बढ़ी। निजी निवेश ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। इसके कारण वृद्धि का एक ऐसा चक्र शुरू हुआ जिसमें उत्पादन ढांचा उन पूंजी प्रोत्साहन वाली वस्तुओं की ओर स्थानांतरित हो गया जिनका उपभोग शीर्ष 15 प्रतिशत लोग करते हैं। मनरेगा जैसे कल्याणकारी कदमों और मध्यम वर्ग के आवास में तेजी ने इसे झटका भी दिया। आवास बाजार ने विनिर्माण क्षेत्र के रोजगारों को बढ़ावा दिया। निर्यात और कृषि क्षेत्र के प्रदर्शन ने प्राय: घरेलू मांग की पूर्ति की। उच्च वृद्धि से राजकोषीय गुंजाइश बनती है जिसका इस्तेमाल खाद्य सब्सिडी देने और गरीबी हटाने में किया जाता है।

मध्यम अवधि में इस मॉडल के कामयाब होने की गुंजाइश नहीं दिखती क्योंकि मौजूदा मंदी संकेत देती है कि इसकी सीमाओं ने अर्थव्यवस्था पर अपेक्षाकृत जल्दी असर डाला है। शीर्ष आय वर्ग की मांग में संतृप्ति आ रही है लेकिन कम आय वाले लोग उन चीजों को अभी भी नहीं खरीद पा रहे हैं जो शीर्ष संकेतकों में आती हैं। अब तक जो क्षेत्र वृद्धि के वाहक रहे हैं वे अब धीमे पड़ रहे हैं। परंतु निवेश में इसलिए कमी आई है क्योंकि यह अन्य क्षेत्रों में मांग की स्थिति पर प्रतिक्रिया दे रहा है। अन्य क्षेत्र भी गति नहीं पकड़ रहे हैं जबकि कृषि क्षेत्र में कमजोर प्रदर्शन से हालात और अधिक बिगड़ रहे हैं। निर्यात और बढ़े हुए सरकारी निवेश से मांग की ढांचागत समस्या के हल होने की बात कही जाती रही है लेकिन हमारे देश की वृद्धि निर्यात आधारित नहीं है। निर्यात घरेलू मांग के पूरक काम करता है लेकिन वह कभी वृद्धि का वाहक नहीं रहा है। अगर यह सिलसिला जारी रहा तो ढांचागत समस्या दूर नहीं होगी। सार्वजनिक निवेश सीमित घरेलू वित्तीय बचत के कारण बाधित है। केंद्र के राजकोषीय घाटे का 65 फीसदी खपत व्यय की पूर्ति में लग जाता है। कर प्राप्ति में भी बहुत अधिक सुधार की आशा नहीं है क्योंकि मंदी का दौर चल रहा है। ढांचागत मांग की समस्या को देखते हुए वृद्धि संबंधी नीति में सस्ती दरों के माध्यम से लाभ उठाना चाहिए। कम से कम न्यूनतम वेतन वालों के लिए कीमतों को व्यवहार्य बनाना चाहिए।

ग्रामीण भारत को एक ऐसा स्थान माना जाता है जहां हमने खाद्य संकट दूर किया। इस दौरान आय और मांग के सवालों को धता बताया जा रहा। सस्ते आवास भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां निजी निवेश आर्थिक गतिविधियों और रोजगार को बढ़ावा दे सकता है। न्यूनतम आय वाले लोगों पर ध्यान केंद्रित कर ऐसा किया जा सकता है।

हम देश में अमीरों के लिए कपड़े बनाते हैं जबकि न्यूनतम आय वालों के लिए सस्ते कपड़े बांग्लादेश और वियतनाम से आयात किए जाते हैं। वस्त्र क्षेत्र को प्रतिस्पर्धी बनाने और शुद्ध आयात कम करने से वृद्धि और रोजगार को बढ़ावा मिल सकता है।

स्वास्थ्य और शिक्षा दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां 20 वर्ष से मांग व्यापक है। अमीर इस मामले में आयात पर भरोसा करते हैं और इसलिए उनकी मांग पर आधारित कारोबारी मॉडल नाकाम हो रहे हैं। सस्ती लेकिन बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की मांग न्यूनतम वेतन वाले लोगों में ज्यादा है। इससे आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में भी इजाफा होगा। मौजूदा कारोबारी मॉडल इस मांग को पूरा करने में असमर्थ है।

अगले स्तंभ में मैं उन वृहद आर्थिक नीतियों की चर्चा करूंगा जिनके बारे में माना जा सकता है कि वे अल्पावधि में मंदी के असर से बचा सकती हैं लेकिन मध्यम अवधि में हमें मांग की ढांचागत समस्या को दूर करना होगा। आपूर्ति क्षेत्र की बाधाएं सही हैं लेकिन उनको हल करते हुए मांग क्षेत्र की बाधाओं को धन में रखना होगा।

कठिनाई भरे आर्थिक हालात को नकार नहीं रहे प्रधानमंत्री मोदी

दिल्ली डायरी

ए के भट्टाचार्य

प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए पहले साक्षात्कार पर मीडिया की करीबी निगाह रहती है और वह उसका विश्लेषण भी करता है। इस सप्ताह के आरंभ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई सरकार के गठन के बाद पहला साक्षात्कार द इकनॉमिक टाइम्स को दिया। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अपने पहले साक्षात्कार के लिए एक आर्थिक अखबार को चुना जबकि उनकी नई सरकार काफी हद तक राजनीतिक एजेंडे पर चल रही है।

साक्षात्कार के कुछ दिन पहले ही उनकी सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया था और संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को लगभग निष्प्रभावी कर दिया था। सरकार ने राज्य को दो केंद्र शासित क्षेत्रों में बांटने की घोषणा भी की। जाहिर है, एक सामान्य समाचार पत्र को साक्षात्कार देकर इस कदम पर सरकार के नजरिये को स्पष्ट करना शायद अधिक उचित समझा जाता।

प्रधानमंत्री द्वारा आर्थिक अखबार का चयन करने और अर्थव्यवस्था के बारे में बातचीत करने के भी उचित कारण हैं। अर्थव्यवस्था की गिरती हालत और पहले बजट पर बाजार तथा देश के उद्योग जगत की व्यापक तौर पर नकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद शायद साक्षात्कार के जरिये इन मुद्दों पर बात करना जरूरी हो गया था। देश की आर्थिक वृद्धि दर जनवरी-मार्च 2019 में घटकर 5.8 फीसदी रह गई और आने वाली तिमाही में हालात और खराब रहने की आशंका है। निर्यात वृद्धि चिंता का विषय है और शेयर बाजार को भी काफी नुकसान हुआ है। खासतौर पर बजट में बड़े अमीरों पर कर लगाने के प्रावधान का असर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के बड़े तबके पर भी पड़ना तय है।

ऐसे में शायद ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कारोबारियों में यह भावना बढ़ रही थी कि मोदी सरकार राजनीतिक एजेंडे पर अधिक केंद्रित है और अर्थव्यवस्था पर कम। साक्षात्कार को यह संदेश देने का उचित माध्यम माना गया कि मोदी अर्थव्यवस्था और उसकी समस्याओं को लेकर चिंतित हैं। साक्षात्कार में जम्मू कश्मीर को लेकर बात नहीं हुई, सारा जोर आर्थिक मुद्दों पर रहा।

साक्षात्कार से दो संदेश एकदम स्पष्ट रूप से सामने आए। पहला संदेश बैंकरों तथा उद्योग जगत के अन्य नेताओं के लिए था। बैंकरों को आवश्स्त किया गया कि उनके द्वारा दिए जाने वाले कर्ज को लेकर उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। उनसे यह भी कहा गया कि वे ऐसी दरों पर ऋण दें जो अर्थव्यवस्था की कम मुद्रास्फीति को परिलक्षित करे। इसी तरह मोदी ने उद्योग जगत से आग्रह किया कि वे निवेश बढ़ाएं। उन्होंने कारोबारियों को आश्वस्त किया कि कानून का पालन करने वालों को सरकार का पूरा समर्थन मिलेगा। उन्होंने बेईमान कर अधिकारियों के खिलाफ उठाए गए कदमों का भी जिक्र किया।

दोनों संदेश ऐसे समय में आए हैं जबकि उद्योगपतियों और बैंकरों के शोषण की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं जहां कर अधिकारी अपने लक्ष्य पूरे करने के लिए कारोबारियों और व्यापारियों को अधिक कर संग्रह के लिए परेशान करते रहे हैं। सरकारी बैंकर इस डर से ऋण देने में आनाकानी करते रहे कि कहीं कानून प्रवर्तन एजेंसियां उनके खिलाफ मामला न दर्ज कर लें। यही कारण है कि कारोबारी नेताओं और व्यापारियों के पास संसाधनों की कमी बनी रही।

मोदी ने दो विशिष्ट उल्लेख किए। उन्होंने व्यक्तिगत आंकड़ों पर व्यक्ति के अधिकार को उतना ही महत्त्वपूर्ण बताया जितना कि निजी संपत्ति पर उसका अधिकार है। यह वक्तव्य डेटा को लेकर व्यापक चिंता को हल नहीं करता है लेकिन यह बड़ी बहुराष्ट्रीय डिजिटल कंपनियों को एक संदेश तो देता है। ये कंपनियां सरकार की डेटा स्थानीयकरण की नीति से खफा हैं। सरकार जोर देती रही है कि भारतीय डेटा से काम करने वाली विदेशी कंपनियों को अपना डेटा भारत में रखना होगा और उन पर भारतीय कानून लागू होंगे। जाहिर है विदेशी कंपनियों ने मोदी का संदेश सुन लिया होगा।

उनका दूसरा जोर वाहन उद्योग पर था जो कारों की मांग में आई भारी कमी से हिला हुआ है। ऐसे समय में जबकि विभिन्न सरकारी विभाग पारंपरिक जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों को चलन से बाहर करने की योजना पर काम कर रहे हैं और उनकी जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल लाना चाह रहे हैं, मोदी ने कहा कि देश का बाजार इतना बड़ा है कि यहां पारंपरिक वाहन और इलेक्ट्रिक वाहन दोनों की खपत है। उन्होंने कहा कि दोनों तरह के वाहन साथ-साथ चल सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने कई आश्वस्त करने वाले वक्तव्य दिए, मसलन राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, बैंक, पेंशन, बीमा और बिजली क्षेत्रों में और सुधार तथा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और श्रम सुधार के मानकों पर और अधिक उदारीकरण की बात। उनकी बातों से लगा कि आने वाले दिनों में सरकारी कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी की बिक्री बढ़ेगी।

उन्होंने यह संकेत दिया कि सरकार टोल रोड और पुलों को निजी क्षेत्र को बेचकर उससे मिलने वाले संसाधन का इस्तेमाल नई बुनियादी परियोजनाओं में निवेश के रूप में करने के पुराने विचार से दूर हो रही है। जिन लोगों को आशा थी कि सरकार अपनी जेब ढीली कर ऐसी बुनियादी परियोजनाओं पर और अधिक खर्च करेगी, वे इससे निराश होंगे। नई पूंजी जुटाने के लिए परिसंपत्ति पुनर्चक्रण के बारे में सरकार गंभीरता से नए सिरे से विचार कर रही है।

ये तमाम आश्वस्तिकारक संदेश उद्योग और बाजार का मिजाज बदल पाएंगे या नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। सुधार की ऐसी प्रतिबद्धताओं तथा नीतिगत पहलों से होने वाले आर्थिक लाभ भी इस बात पर निर्भर करेंगे कि इन्हें कितनी जल्दी और प्रभावी ढंग से अंजाम दिया जाता है। परंतु प्रधानमंत्री ने इन मसलों पर बात करने के लिए एक अखबार को साक्षात्कार देना उचित समझा, यह दर्शाता है कि वह इन बातों को नकार नहीं रहे हैं। शायद उन्हें पता चल गया है कि अर्थव्यवस्था पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।

कानाफूसी

सोने का अंडा देने वाली मुर्गी!

ट्विटर पर सक्रिय रहने वाले लोगों ने देश के वाहन उद्योग और सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के किस्से में एक सिलसिला तलाश कर लिया है। कहानी के मुताबिक एक किसान के पास एक मुर्गी थी जो सोने के अंडे देती थी। लेकिन वह एक दिन में एक ही अंडा देती थी। किसान ने लालच में आकर मुर्गी को मार दिया ताकि एक ही बार में सारे अंडे निकाल सके। जाहिर है उसे जो एक अंडा मिलता था, वह भी बंद हो गया। ट्विटर इस्तेमाल करने वालों का कहना है कि उस कहानी का किसान ही आज की केंद्र सरकार है और वह मुर्गी है देश का वाहन उद्योग। अंडे को उन्होंने वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी का नाम दिया है। एक अनुमान के मुताबिक विनिर्माण क्षेत्र के जीडीपी में वाहन उद्योग की हिस्सेदारी 49 फीसदी है और कुल जीएसटी संग्रह में वह 15 फीसदी योगदान देता है।

द्विराष्ट्र सिद्धांत पर चर्चा

नानाजी देशमुख द्वारा चार दशक से भी पहले स्थापित दीनदयाल शोध संस्थान 32 वर्षों से 15 अगस्त को अखंड भारत परिसंवाद का आयोजन कर रहा है। इस वर्ष इस परिसंवाद के प्रमुख वक्ता होंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरिफ मोहम्मद खान। खान ने मुस्लिम महिला विधेयक के मसले पर राजीव गांधी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था और हाल ही में उन्होंने तीन तलाक मसले पर मौजूदा केंद्र सरकार का समर्थन किया। उपरोक्त आयोजन में खान धर्मनिरपेक्षता और द्विराष्ट्रवाद नामक विषय पर अपनी बात रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के उपाध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे इस अवसर पर दूसरे वक्ता होंगे। यह शोध संस्थान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से वैचारिक जुड़ाव रखता है।

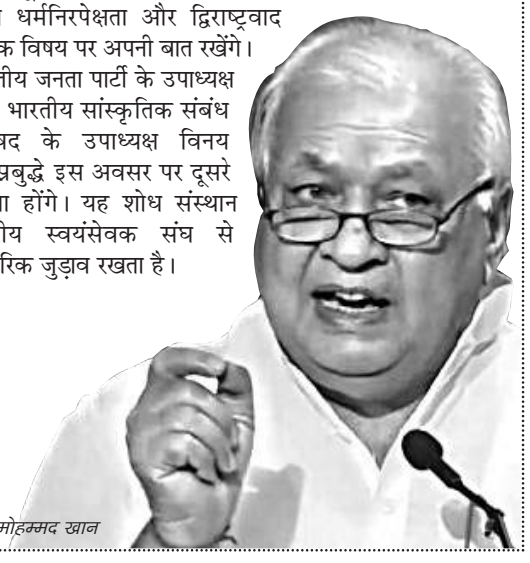

आरिफ मोहम्मद खान

आपका पक्ष

सीएसआर नियमों का पालन जरूरी

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के नियमों को नहीं मानने पर तीन साल की जेल हो सकती है। हाल में नीतिगत बदलावों में यह प्रावधान किया गया था। हालांकि इस मामले में गठित समिति ने नियम के उल्लंघन को दीवानी अपराध बनाने और केवल जुर्माना लगाने की सिफारिश की है। सीएसआर किसी कंपनी का सामाजिक दायित्व होता है। कंपनी सामाजिक विकास में योगदान देती है और एक निश्चित राशि खर्च करती है। इससे कंपनियों को कर में छूट मिलती है। कई कंपनियां कर में छूट पाने के लिए सीएसआर में अधिक खर्च दिखाती हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर समाज के विकास में कोई राशि खर्च नहीं की जाती है। सरकार की यह पहल सामाजिक उत्थान की है जिसका जिम्मा कंपनियों को दिया गया है। कंपनियां शिविर लगाकर या अपने कार्यालय में लोगों को बुलाकर

शिक्षित करती हैं। उन्हें प्रशिक्षण देती हैं तथा उनके बीच जागरूकता लाती हैं। लेकिन क्या सीएसआर के तहत होने वाले कार्यों की समीक्षा सरकारी स्तर पर की जाती है। कंपनियां अपने द्वारा सीएसआर के तहत किए जाने वाले कार्यों की पूरी रिपोर्ट तैयार करती हैं। लेकिन उन रिपोर्ट की कभी जांच होती है कि वास्तव में लोगों को इससे

सीएसआर नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर जुर्माने की सिफारिश की गई है

फायदा हुआ है। इसके लिए सरकारी स्तर पर जांच होनी चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि कंपनियां सिर्फ कागजों पर ही सीएसआर गतिविधियों को अंजाम दे रही हो और सरकार से कर पर भारी छूट का लाभ उठा रही हों। अत: सरकार को अपने द्वारा दी जाने वाली छूट की समीक्षा करने का पूरा अधिकार है तथा सीएसआर कानून का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर कठोर कार्रवाई करना जरूरी है।

कोमल शर्मा, नई दिल्ली

धरती के स्वर्ग में शांति की कवायद

जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बनाने के बाद वहां शांति बहाल करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर में पथराव की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई थी। कश्मीर के युवा सेना के जवानों पर पत्थर बरसाते थे। इन युवाओं में स्कूल-कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र तथा छात्राएं भी होती थीं। किसी देश में सेना पर हमला करना राष्ट्रद्रोह माना जाता है। लेकिन केंद्र सरकार ऐसे पत्थरबाजों पर कड़ी कार्रवाई करने के बजाय सिर्फ आंसू गैस छोड़कर भीड़ को हटाने का प्रयास करती थी। केंद्र सरकार या सेना के जवानों का देश नागरिकों पर अत्याचार करने की घटना शायद ही सामने आई हो। अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। केंद्र सरकार किसी भी हिंसा को रोकने के लिए कड़ाई बरत रही है जिसका परिणाम कश्मीर में शांति बरकरार है। अभी तक कश्मीर में कहीं भी पथराव की घटना सामने नहीं आई है। कश्मीर में अलगाववादी गुट ही स्थानीय लोगों को सरकार के खिलाफ भड़काते थे। उन्हें यह निर्देश पाकिस्तान तथा उसके कब्जे वाली जगह में रह रहे आतंकवादियों से मिलती थी। अब अलगाववादी नजरबंद हैं या फिर जेल में हैं। इससे कश्मीर में अबतक हिंसा की कोई घटना नहीं हुई है। अत: आने वाले दिनों में धरती का स्वर्ग कश्मीर फिर से अपनी नई पहचान बनाने में सफल होगा।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।